केंद्रीय सहायता के वितरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानदंड में भारांश के माध्यम से तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से, इस संबंध में राज्यों की सहायता करता हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Proposal for making Visakhapatnam as Export Promotion Zone

2121. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Visakhapatanam is proposed to be made an export promotion zone having latest infrastructual facilities;

(b) if so, the details thereof with background including amount involved in such initiatives;

(c) whether the Central Government propose to share the funds of the project;

(d) if so, the details thereof and if not the reasons therefor;

(e) whether Government propose to ask other State Government of coastal areas to take up similar projects like the one undertaken by Andhra Pradesh Government; and

(f) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (f) The Export Processing Zone set up by the Central Govt, at Visakhapatnam is operational since 1.4.1993. Basic infrastructure facilities in the first phase covering an area of 163 acres have been completed. The expenditure so far incurred is Rs. 15.92 crores. In accordance with the practice, the expenditure in respect of provision of infrastructure within the Zone is entirely met by the Central Government. Keeping in view the availability of funds and the need to optimise the infrastructural facilities in the existing Export Processing Zones, there is no proposal at present for the Central Government to set up new Zones in the Country. However, Export Processing Zones can now also be established by the State Governments or in the joint/private sectors after obtaining the approval of the Government of India.

कृषि मजदूरों की संख्या

2122. **श्री नागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री 7 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 855 के दिए गए उत्तर को दखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) कृषि मजदूरों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी-कितनी हैं; और

(ख) इन मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (**श्री जी. वेंकट स्वामी**) : (क) एक विवरण संलग्र हैं (नीचे देखिए)।

(ख) समस्या को एक बहुत आयामी कार्रवाई, अर्थात् ग्रामीण अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करके, गैर-फार्म कार्यकलापों के विविधीकरण, कौशल सुधार कार्यक्रमों, स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और भू-संसाधनों आदि का अधिक से अधिक उपयोग करके निपटाने की अपेक्षा की गई हैं। 1993-94 से दो और अधिक महत्वपूर्ण मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को, अर्थात् गहन जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) को देश में 120 पिछड़े जिलों में तथा रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) को देश में 2000 पिछड़े और जनजातीय ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा हैं।